सीपीसीटी पदोन्नति में बाधक नहीं बनेगी

15 हजार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति की राह खुली

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 12 अगस्त. प्रदेश के 15 हजार से अधिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति की राह अब खुल गई है. इस संवर्ग की पदोन्नति की राह की सबसे बड़ी बाधा सीपीसीटी परीक्षा की अनिवार्यता अब नहीं रहेगी.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को इस संबंध में बड़ी घोषणा की. उन्होंने कहा कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति में सीपीसीटी परीक्षा बाधक नहीं बने. उन्होंने निर्देश दिए कि तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति में सीपीसीटी परीक्षा को उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता पर जल्द सकारात्मक निर्णय लिया जाए. यह सुनिश्चित करें कि सभी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पात्र कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिले. सीपीसीटी परीक्षा के कारण कोई भी तृतीय-चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी पदोन्नति से वंचित या रिवर्ट नहीं हो.

यहां बता दें कि सामान्य प्रशासन विभाग ने 22 जुलाई को आदेश जारी कर पदोन्नति के लिए सीपीसीटी की परीक्षा पास करने की अनिवार्यता रख दी थी. आदेश में कहा गया था कि जिनके पास यह डिग्री नहीं होगी, वे पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे.

22 जुलाई को किए थे आदेश जारी

पदोन्नति की कार्यवाही को कर दिया था निरस्त

इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने पदोन्नति की कार्यवाही को निरस्त कर दिया था और जिनको पदोन्नति दी गई थी, उन्हें वापस रिवर्ट कर दिया गया था. सामान्य प्रशासन विभाग के इस निर्णय के बाद प्रदेश के कर्मचारी संगठनों ने जबर्दस्त विरोध शुरू कर दिया था, वे जीएडी के इस आदेश को निरस्त करने की मांग कर रहे थे. जीएडी ने अनुकंपा नियुक्ति के मामले में भी सीपीसीटी की अनिवार्यता लागू कर दी है, इसके चलते ऐसे शासकीय सेवक जिनकी असमय मृत्यु हो गई, उनके परिजन अनुकंपा नियुक्ति से वंचित होने लगे हैं. इस निर्णय भी लगातार विरोध हो रहा है.

बगीचे में जैन संत का अंतिम संस्कार

नव भारत न्यूज

इंदौर, 12 अगस्त. बुधवार सुबह शहर के पश्चिम क्षेत्र में स्थित जैन कॉलोनी के सार्वजनिक बगीचे में बिना अनुमति जैन संत का अंतिम संस्कार कर दिया गया. इसकी जानकारी मिलते ही बगीचे में रहवासियों की भीड़ इकठ्ठा हो गई. लोगों ने उक्त घटना का विरोध करना शुरू कर दिया.

मामले की जानकारी मिलते पुलिस मौके पर पहुंची. खास बात यह है कि घटना की पूरी जानकारी पुलिस ने नगर निगम को भेज दी. नगर निगम झोन 15 के वार्ड 72 में स्थित जैन कॉलोनी के विद्यासागर सार्वजनिक बगीचे में दिगम्बर जैन समाज के लोगों ने बिना अनुमति के जैन संत सुलभाघी सागर की अंत्येष्टि कर दी. दिगंबर जैन समाज के लोगों ने अन्नपूर्णा पुलिस से रात को बगीचे में अंत्येष्टि करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन पुलिस ने अनुमति नहीं दी. बावजूद इसके सुबह जल्दी 6 बजे दिगम्बर जैन समाज ने बिना अनुमति के जैन संत का दह संस्कार कर दिया.

पंचनामा बनाया : पार्षद

उक्त मामले में क्षेत्रीय पार्षद योगेश गेंदर ने कहा कि नगर निगम के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा बना लिया है, आगे की कार्रवाई निगम करेगा. उल्लेखनीय है कि 80 वर्षीय जैन संत वर्षा योग (चातुर्मास) के लिए क्षेत्र में ठहरे हुए थे. इसी दौरान उनका निधन हो गया.

बारिश से राजधानी की सड़कें उखड़ीं

लोनिवि मंत्री ने मंत्रालय में बुलाई अफसरों की बैठक

तत्काल मरम्मत का काम शुरू करने के निर्देश

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 12 अगस्त. राजधानी में पिछले चार दिनों से हो रही बारिश ने शहर की सड़कों की परतें उधेड़ दी हैं, जिसके चलते सड़कों में बड़े- बड़े गड्ढे हो गए हैं, इतना ही नहीं ओव्हर ब्रिज से लेकर फ्लायओवर तक में गड्ढे नजर आ रहे हैं, पानी के भराव के चलते वाहन चालकों के लिए गाड़ी चलाना आसान नहीं रहा, दुर्घटना की लगाातार आशंका बनी रहती है.

इस बीच अब पेंचवर्क की तैयारी भी की जा रही है. लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने भोपाल में विभाग की क्षतिग्रस्त सड़कों और विभिन्न स्थानों पर हुए गड्ढों को गंभीरता से लिया है. उन्होंने तत्काल मरम्मत के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि बारिश के कारण नागरिकों को आवागमन में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए. सड़कों को सुरक्षित और सुगम बनाए रखना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है. लोनिवि मंत्री ने बुधवार को मंत्रालय में लोक निर्माण विभाग के आला अफसरों की बैठक बुलाई और स्थिति की समीक्षा की, इस दौरान मंत्री ने भोपाल की सड़कों की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्य अभियंता ब्रिज एवं मुख्य अभियंता भोपाल को निर्देशित किया कि वे आज ही शहर की प्रमुख सड़कों, पुलों और यातायात की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों का गहन निरीक्षण करें.

स्थायी मरम्मत तत्काल संभव नहीं है

मंत्री ने कहा कि वर्षा के कारण जहां डामरीकरण अथवा स्थायी मरम्मत तत्काल संभव नहीं है, वहां क्विक सेट सीमेंट, पेवर ब्लॉक अथवा अन्य उपयुक्त तकनीक का उपयोग कर गड्ढों को तुरंत भरा जाए. सुधार कार्य इस प्रकार किया जाए कि नागरिकों को शीघ्र राहत मिले और वाहनों का सुरक्षित एवं सुविधाजनक आवागमन सुनिश्चित हो सके.

तिरंगा यात्रा राष्ट्रीय एकता को मजबूत करेगी

मुरैना. मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि तिरंगा यात्रा राष्ट्रप्रेम और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करने के साथ ही देश के प्रति गौरव की भावना को जन-जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है. तोमर बुधवार को 'हर घर तिरंगा अभियान' के अंतर्गत मुरैना में निकाली गई विशाल पैदल तिरंगा यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे. तिरंगा यात्रा पंडित रामप्रसाद बिस्मिल संग्रहालय से प्रारंभ होकर रामजानकी मंदिर, पुरानी जिला पंचायत, गर्ल्स स्कूल रोड, गोपीनाथ की पुलिया, महामाया मंदिर, रूई की मंडी, हनुमान चौराहा, पुल तिराहा और पुरानी कलेक्ट्रेट होते हुए पुन: पंडित रामप्रसाद बिस्मिल संग्रहालय पहुंचकर संपन्न हुई.

लो-प्रेशर ब्रेक : मप्र में 5 दिन तक बारिश का दौर

भोपाल समेत अधिकांश जिलों में बिजली और तेज हवा का अलर्ट

नवभारत न्यूज

भोपाल, 12 अगस्त. मध्य प्रदेश में मानसून ने फिर जोर पकड़ लिया है. उत्तर-पश्चिमी मप्र पर बने कम दबाव के क्षेत्र, मानसूनी ट्रफ और ऊपरी हवा के चक्रवात के असर से बुधवार से प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है.

मौसम विभाग ने श्योपुरकलां में अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जबकि मालवा-निमाड़, चंबल-ग्वालियर, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के कई जिलों में गरज-चमक, तेज हवा और बारिश का अलर्ट है. अगले पांच दिन तक प्रदेश में कहीं कम तो कहीं ज्यादा बारिश की स्थिति बनी रहने का अनुमान है.

मौसम विभाग के अनुसार उत्तर-पश्चिमी मध्य प्रदेश और आसपास के क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है. इसके साथ मानसूनी ट्रफ बीकानेर से होते हुए उत्तर मप्र में कम दबाव वाले इलाके के पास से गुजर रही है. हवा के ऊपरी स्तर पर बना चक्रवात भी नमी खींच रहा है. अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से मिल रही नमी के कारण बादल लगातार बन रहे हैं.

भोपाल में बीते 24 घंटों में 0.59 इंच बारिश दर्ज की गई. शहर में बादल छाए रहने और रुक-रुककर बारिश होने से दिन का तापमान कुछ नरम रहेगा, लेकिन हवा में नमी ज्यादा रहने से उमस बनी रह सकती है. अगले 24 घंटे में गरज-चमक के साथ रिमझिम बारिश का दौर जारी रहेगा, फिसलन और कुछ निचले इलाकों में पानी भरने की स्थिति बन सकती है. इस सीजन की कुल बारिश 32.97 इंच दर्ज की गयी है जो की सामान्य से 7.14 इंच ज्यादा है.

ई-जीरो एफआईआर से 4,888 साइबर अपराध दर्ज

भोपाल, 12 अगस्त. प्रदेश में ई-जीरो एफआईआर व्यवस्था के तहत प्रदेश में अब तक 4,888 साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए जा चुके हैं. 25 दिसंबर 2025 को शुरू हुई इस व्यवस्था के तहत पहले एक लाख रुपये या उससे अधिक की साइबर ठगी पर ई-जीरो एफआईआर दर्ज की जाती थी.

अब इसकी सीमा घटाकर 25 हजार रुपये कर दी गई है. इससे अधिक संख्या में साइबर ठगी के पीड़ितों को त्वरित कानूनी सहायता मिल सकेगी. 25 दिसंबर 2025 से 31 जुलाई 2026 के बीच दर्ज 4,888 ई-जीरो एफआईआर के जरिए पुलिस ने ठगी की रकम को समय रहते रोकने और डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित करने की कार्रवाई की. झाबुआ, डिंडोरी, अशोकनगर, मऊगंज, सिवनी, राजगढ़, आगर-मालवा, बालाघाट, देवास, भोपाल ग्रामीण, मंडला, मैहर, बैतूल, अलीराजपुर, नर्मदापुरम, सीधी और खंडवा जिलों का प्रदर्शन बेहतर रहा. पुलिस के अनुसार साइबर ठगी के बाद शुरुआती कुछ घंटे बेहद महत्वपूर्ण होते हैं.

पीड़ितों को तत्काल 1930 साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत करनी चाहिए. समय पर शिकायत मिलने से ठगी की रकम को अपराधियों के खातों से निकलने से पहले रोकने की संभावना बढ़ जाती है.

5000 पौधे रोपकर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

ग्वालियर. ग्वालियर में हरियाली अमावस्या के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण और शहर को हरा-भरा बनाने के संकल्प के साथ जिला प्रशासन एवं नगर निगम द्वारा विशाल पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया. आगरा-झांसी बायपास स्थित रमौआ बांध के समीप बन रहे नवीन ई-बस स्टैंड एवं होटल मैरियट के पास आयोजित कार्यक्रम में एक ही दिन में करीब पांच हजार पौधे रोपे गए. कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ अधिकारियों, आम नागरिकों, समाजसेवी संस्थाओं और शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की.

15 अगस्त को पुलिसकर्मी होंगे सम्मानित

विशेष संवाददाता

भोपाल, 12 अगस्त . स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को लाल परेड मैदान में आयोजित होने वाले पदक अलंकरण समारोह में मध्यप्रदेश के 47 पुलिस एवं होमगार्ड कर्मियों को पदकों से सम्मानित किया जाएगा. समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त पदक प्रदान करेंगे.

समारोह में नौ पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक तथा 33 पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किए जाएंगे. इसके अलावा

होमगार्ड एवं सिविल डिफेंस के तीन अधिकारियों-कर्मचारियों को भी सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाएगा. विशिष्ट सेवा पदक प्राप्त करने वालों में वरिष्ठ अधिकारी योगेश देशमुख, मकरंद देउस्कर, राकेश गुप्ता, संतोष कुमार सिंह, मिथिलेश कुमार शुक्ला और अवधेश कुमार गोस्वामी सहित तीन अन्य पुलिसकर्मी शामिल हैं. सराहनीय सेवा के लिए चयनित 33 पुलिसकर्मी प्रदेश के विभिन्न जिलों, विशेष इकाइयों और पुलिस मुख्यालय में सेवाएं दे रहे हैं. समारोह में दो सर्वश्रेष्ठ जीवन रक्षक पदक भी प्रदान किए जाएंगे. ये पदक मरणोपरांत मंदसौर के स्वर्गीय मनोहर सिंह चौहान और दमोह के कार्यवाहक सहायक उप निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद मिश्रा को प्रदान किए जाएंगे.

प्रदर्शन : डीपीआई के सामने बैठेंगे शिक्षक-अभ्यर्थी

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 12 अगस्त. लंबे समय बाद जब मध्यप्रदेश सरकार ने प्राथमिक वर्ग 1, 2 और 3 को नियुक्ति देने का निर्णय लिया. तो उसमें में लोक शिक्षा संचालनालय और शिक्षा विभाग की गड़बड़ियों के कारण 1000 से अधिक वर्ग 3 के शिक्षकों की नियुक्ति पर तलवार लटक गई है. जहां एक तरफ ये शिक्षक दो दो परीक्षाएं पास कर योग्यता के पैमाने पर खरे उतरे हैं.

वहीं दूसरी तरफ डीपीआई की तरफ से जारी कुछ आदेशों और नियमों में हुई गड़बड़ी विभाग की लापरवाही को दर्शाती है. नियुक्ति की मांग को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी एक बार फिर गुरुवार से डीपीआई के सामने प्रदर्शन करने जा रहे हैं. अभ्यर्थियों का कहना है कि बीते दिनों लोक शिक्षण आयुक्त अभिषेक सिंह से बातचीत में उन्होंने विभाग की तरह से हुई लापरवाही को तो स्वीकार कर लिया है, लेकिन नियुक्ति के संबंध में अब तक कोई स्पष्ट जवाब देने को तैयार नहीं है. विभाग ने हवाला दिया है कि अगर अब नियमों में बदलाव कर नियुक्ति दी जाती है तो अयोग्य अभ्यर्थी भी नियुक्ति के लिए

प्रदर्शन पर बैठ सकते हैं. इस कारण नियुक्ति देने के विषय पर संशय बना हुआ है. जिसको लेकर अभ्यर्थियों ने निराशा जाहिर करते हुए कहा कि विभाग की गलतियों का भुगतान वो अपनी नौकरी और भविष्य को संकट में डालकर नहीं कर सकते.

क्या है मामला

विभाग द्वारा पहले जारी नियम क्रमांक 49 के तहत कहा गया था कि प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा वर्ग 3 के शिक्षक अभ्यर्थी जो अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं, वह भी परीक्षा में बैठने के पात्र माने जाएंगे. इसमें अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग के पूर्व शैक्षणिक योग्यता के प्रमाणपत्र की तिथि तक दस्तावेज पूर्ण होने चाहिए. लेकिन दस्तावेज सत्यापन के कुछ दिन पहले ही विभाग ने नियम में बदलाव करते हुए योग्यता पूर्ण करने की तिथि 25 अगस्त 2025 घोषित कर दी. जिससे हजारों की संख्या में जो अभ्यर्थियों ने 2026 में योग्यता पूरी की वो अयोग्य घोषित हो गए.

शिक्षकों को संचालनालय में होना होगा हाजिर

भोपाल. लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) ने प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2026 के तहत चयनित अभ्यर्थियों को परस्पर जिला परिवर्तन यानी म्यूचुअल ट्रांसफर की बड़ी राहत दी है. इसके तहत अनारक्षित वर्ग में चयनित एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थी अपने मूल वर्ग या चयनित वर्ग, दोनों में से किसी भी वर्ग के उम्मीदवार के साथ जिला बदलने के लिए आवेदन कर सकते हैं. वहीं तकनीकी कारणों से 10 अगस्त को पोर्टल शुरू न हो पाने के कारण विभाग ने अभ्यर्थियों को 10, 11 और 12 अगस्त तक एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करने की सुविधा दी थी.

आदिवासी बच्चों की मौत पर दिग्विजय चिंतित

पिछले एक सप्ताह में 11 आदिवासी बच्चों की मौत का दावा

विशेष संवाददाता

भोपाल, 12 अगस्त . पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बालाघाट जिले के आदिवासी बहुल बिरसा ब्लॉक में दूषित पानी और संक्रामक बीमारियों से आदिवासी बच्चों की मौतों पर गंभीर चिंता जताते हुए पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है.

मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में सिंह ने दावा किया कि पिछले एक सप्ताह में 11 आदिवासी बच्चों की मौत हुई है, जबकि जिला प्रशासन ने सात मौतों की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि बालाघाट जिला अस्पताल में 100 से अधिक बच्चों के भर्ती होने की जानकारी है, जिनमें करीब 40 से 50 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है.

सिंह के अनुसार बोंडारी, कुंडेकसा, कोरका और आसपास के गांवों में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. इन क्षेत्रों में मलेरिया, निमोनिया, बुखार, खांसी-जुकाम और त्वचा संबंधी बीमारियों के मामले सामने आने का दावा किया गया है. उन्होंने दूषित पानी और प्रशासनिक लापरवाही को संकट की संभावित वजह बताया.

उन्होंने मामले की राज्यस्तरीय जांच कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. साथ ही वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों और विशेषज्ञ चिकित्सकों को प्रभावित गांवों में भेजकर चिकित्सा शिविर लगाने को कहा. गंभीर रूप से बीमार बच्चों को नागपुर, रायपुर या भोपाल एयरलिफ्ट कर सरकारी खर्च पर उपचार कराने तथा मृत बच्चों के प्रत्येक परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की मांग भी की गई है.

भोपाल रेलवे स्टेशन पर गूंजा देशभक्ति का संगीत

भोपाल, 12 अगस्त. स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भोपाल स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल बैंड की शानदार संगीतमय प्रस्तुति आयोजित की गई. प्लेटफॉर्म नंबर-1 पर आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत गीतों और धुनों ने स्टेशन परिसर को देशप्रेम के रंग में रंग दिया.

भोपाल मंडल रेल प्रबंधक पंकज त्यागी ने कार्यक्रम में पहुंचकर आरपीएफ बैंड की प्रस्तुति का उत्साहवर्धन किया. बैंड के जवानों ने 'वंदे मातरम्' सहित कई देशभक्ति गीतों की मनमोहक प्रस्तुति दी, जिसे रेलवे कर्मचारियों, यात्रियों और उपस्थित आमजन ने खूब सराहा. कार्यक्रम

के दौरान स्टेशन परिसर में 'वंदे मातरम्' और 'यशो लभस्व' लोगो से सुसज्जित विशेष सेल्फी प्वाइंट भी बनाया गया. यह यात्रियों और आमजन के लिए आकर्षण का केंद्र रहा.

मिसरोद रेलवे फाटक 13 से 16 अगस्त तक रहेगा बंद

भोपाल. पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल के मिसरोद स्टेशन के पास स्थित समपार फाटक क्रमांक 246 को ट्रैक अनुरक्षण कार्य के चलते 13 से 16 अगस्त तक अस्थायी रूप से बंद रखा जाएगा. इस दौरान फाटक से आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. रेलवे के अनुसार, फाटक बंद रहने की अवधि में वाहन चालक और आम नागरिक मिसरोद स्थित एलएचएस (लिमिटेड हाइट सबवे) तथा बावड़िया कलां और अहमदपुर स्थित रोड ओवरब्रिज एवं अंडरपास का उपयोग कर सकेंगे. रेलवे ने नागरिकों और वाहन चालकों से अपील की है कि निर्धारित अवधि में बंद फाटक से आवागमन करने के बजाय वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें.

पेज एक के शेष

वन विभाग का क्लर्क निकला करोड़ों का आसामी

के खिलाफ भ्रष्टाचार और काली कमाई से अकूत संपत्ति बनाने की शिकायत मिली थीं. प्राथमिक जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद,क्लर्क श्वेतांक चौरसिया के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया. ईओडब्ल्यू जबलपुर ने जाल बिछाया. बुधवार सुबह ठीक 6 बजे दो अलग-अलग टीमों ने आरोपी श्वेतांक के इंदिरा जी वार्ड नंबर-2, मण्डला स्थित निवास पर एक साथ दबिश दी. अचानक हुई इस कार्रवाई से क्लर्क के परिवार को संभलने का मौका तक नहीं मिला.

सर्च में ये मिला: सर्चिंग के दौरान जांच ईओडब्ल्यू को आरोपी और उसके करीबियों के नाम पर कई अचल संपत्तियों के दस्तावेज, नगदी और जेवरात मिले हैं. ईओडब्ल्यू के मुताबिक मण्डला में करीब 1.50 करोड़ की अनुमानित लागत का मकान, 51.50 लाख कीमत की एक दुकान, 85 ग्राम सोने के जेवरात कीमत 13 लाख और करीब 2.8 किलोग्राम चांदी कीमत 6 लाख, घर से 5 लाख नगद और करीब 25 लाख मूल्य का महंगा घरेलू सामान, 8 लाख की एक फोर-व्हीलर और 1.50 लाख की दो मोटर साइकिलें बरामद की गई हैं.

आजादी से जनविश्वास की आवाज तक के 9 दशक

बदौलत उन्होंने नवभारत को देश के एक प्रमुख व प्रतिष्ठित पत्र समूह का बृहद स्वरूप प्रदान किया. भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 20 नवंबर 2012 को श्री रामगोपाल जी माहेश्वरी की जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर उनकी स्मृति में 5 रुपये का एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था.

आलोक शर्मा ने सीए के लिए संरक्षण कानून बनाने का मुद्दा उठाया

भोपाल. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (सीए) को क्लाइंट विवादों के कारण होने वाले अनावश्यक पुलिस उत्पीड़न से संरक्षण देने के लिए प्रभावी कानूनी व्यवस्था बनाने का प्रश्न लोकसभा में पूछा. भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने बुधवार को लोकसभा में नियम 377 के अंतर्गत इस महत्वपूर्ण विषय को उठाते हुए सरकार का ध्यान चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की समस्याओं की ओर आकर्षित किया. सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट देश की अर्थव्यवस्था, कर व्यवस्था, वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

राजनीति | किसान कल्याण वर्ष के दावों पर पटवारी ने मांगा आंकड़ों का हिसाब

किसानों को मंच नहीं, मुनाफा चाहिए : पटवारी

विशेष संवाददाता

भोपाल, 12 अगस्त. मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने 'कृषक कल्याण वर्ष' के तहत सरकार द्वारा किए जा रहे दावों पर सवाल उठाते हुए किसानों की आय, खेती की लागत, फसलों के दाम, कर्ज और फसल बीमा भुगतान से जुड़े ताजा आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग की है.

पटवारी ने कहा कि सरकार को मंचों, महोत्सवों और घोषणाओं से आगे बढ़कर यह प्रमाणित करना चाहिए कि किसानों की आर्थिक स्थिति

वास्तव में सुधरी है. उन्होंने राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 2018-19 में मध्यप्रदेश के 48.4 प्रतिशत कृषि परिवार कर्जदार थे और प्रति कृषि परिवार औसत बकाया कर्ज 74,420 रुपये था. यह आंकड़ा केन्द्र सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया था.

उन्होंने बताया कि एनएसओ के 'सिचुएशन असेसमेंट सर्वे' के अनुसार 2018-19 में मध्यप्रदेश के कृषि परिवार की औसत मासिक आय 8,339 रुपये थी, जो 10,218 रुपये के राष्ट्रीय औसत से कम थी. पटवारी ने सवाल किया कि किसानों को वास्तव में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का लाभ मिल रहा है या नहीं. उन्होंने फसलवार खरीदी, लागत और किसानों को मिली वास्तविक कीमत के आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग की. उन्होंने कहा कि केवल एमएसपी घोषित करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि बाजार भाव गिरने पर किसानों को प्रभावी संरक्षण मिलना चाहिए.

बीज, खाद, कीटनाशक, डीजल, बिजली, मजदूरी और सिंचाई की बढ़ती लागत के साथ अनियमित बारिश, बाढ़ और सूखे से पैदा होने वाले जोखिमों पर भी उन्होंने सरकार से जवाब मांगा. फसल बीमा के तहत जिले और फसलवार निपटाए गए, लंबित दावों तथा वास्तविक नुकसान के मुकाबले दिए गए मुआवजे का विवरण सार्वजनिक करने की मांग की.

पटवारी ने एनसीआरबी के 2024 के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में कृषि से जुड़े 835 लोगों ने आत्महत्या की, जिससे राज्य देश में तीसरे स्थान पर रहा. उन्होंने कहा कि 'कृषक कल्याण वर्ष' तभी सार्थक होगा, जब किसानों की आय बढ़े, लागत घटे, एमएसपी का प्रभावी संरक्षण मिले और मुआवजा समय पर मिले. उन्होंने कहा, 'किसानों को मंच नहीं, मुनाफा चाहिए; घोषणाएं नहीं, गारंटी चाहिए और भाषण नहीं, बाजार चाहिए.